# *जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान और संकटकालीन तैयारी की मजबूती**

*माइकल देवब्रत पात्र*

अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) के अध्यक्ष श्री एलेजांद्रो लोपेज़, आईएडीआई की महासचिव डॉ. ईवा हुपकेस, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, आईएडीआई और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) सचिवालय के सम्माननीय प्रतिनिधि, जमा बीमा एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और पदाधिकारी, केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि, प्रख्यात वक्तागण और पैनलिस्ट, भारत में बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आमंत्रित व्यक्ति, और जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मेरे सहकर्मी, आप सभी को नमस्कार।

डीआईसीजीसी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में और जयपुर में आईएडीआई एपीआरसी की ओर से आप सभी का स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। पिछला सम्मेलन नवंबर 2011 में, अर्थात 13 वर्ष पहले जोधपुर में आयोजित किया गया था जो यहां से अधिक दूर नहीं है। महाराजा सवाई जय सिंह (द्वितीय) II द्वारा 1727 में स्थापित जयपुर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए अद्वितीय है और अपनी वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास और कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह अपनी इमारतों के विशिष्ट रंग के कारण गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगा गया था। जयपुर कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का केंद्र है। यह भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है।

हमारी डीआईसीजीसी टीम ने वर्तमान रुचि के प्रासंगिक विषयों पर सत्र तैयार किए हैं। हमें उम्मीद है कि अगले दो दिनों में वे आपकी रुचि को आकर्षित करेंगे और आपकी सहभागिता बनाए रखेंगे। हम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) और टोकनयुक्त जमा सहित नई वित्तीय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जमा बीमा के दृष्टिकोण पर नज़र डालेंगे। हम जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों और संकट की तैयारी तथा व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रक्रियाओं और नीतिगत ढाँचों को लागू करने की अनिवार्यता पर भी गहन विचार-विमर्श करेंगे। हमारा मानना है कि ये चर्चाएँ वर्तमान में जरूरी हैं क्योंकि ये हमें जमा बीमा को अधिक लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाने में सक्षम बनाएँगी। मुझे यकीन है कि सम्मेलन के दौरान साझा किए गए विचार, ज्ञान और अनुभव इस बहुआयामी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के लिए आगे के मार्ग पर प्रकाश डालेंगे।

यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि जमा बीमा कार्य किसी अर्थव्यवस्था में एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्रणाली के स्वरूप और प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण, अंतिम उपाय के ऋणदाता/ आपातकालीन चलनिधि सहायता (ईएलए) और समाधान के कार्यों की प्रभावकारिता के साथ मिलकर काम करता है और उसे बढ़ाता है। संयुक्त रूप से वे वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास पैदा करते हैं और स्थायी आधार पर वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हैं। यह उस तेज़ गति के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है जिस पर वित्तीय परिदृश्य कई आयामों में विकसित हो रहा है। मैं आभासी सीमा को पार करने वाले जमा बीमा से शुरुआत करूँगा।

## 2. वित्त का डिजिटलीकरण

वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण जमा बीमाकर्ताओं के लिए अपने अधिदेश को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए कई तरह के अवसर लाता है, जिसमें प्रतिपूर्ति, पर्यवेक्षण, समाधान और संचार में आधुनिकीकरण शामिल है। डिजिटलीकरण बड़े पैमाने की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभदायक है। फिर भी जैसा कि मार्च 2023 में कुछ अधिकार क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र में आए दबाव के अनुभव से पता चलता है, कि यह ऑनलाइन बैंकिंग और व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से समन्वय करके जमा निकासी को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक अस्थिरता के दौर के रूप में वित्तीय स्थिरता जोखिमों के खरे होने की स्थिति को बढ़ा सकता

* 13 अगस्त 2024 को जयपुर राजस्थान, भारत में डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी (एपीआरसी) इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। अनूप कुमार, कीर्तन सिंह निंगवाल, धवल संघवी, ईशान कात्याल, पृथ्वीराज हरीश, शोभित अग्रवाल, अरुण विष्णु कुमार से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

है और उसे तेज कर सकता है। वास्तव में, डिजिटल वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ जमा बीमाकर्ताओं को उनके अधिदेश की पूर्ति के संबंध में बुनियादी सवालों को खड़ा कर रही हैं, जैसे नए वित्तीय उत्पादों की संभावित कवरेज; संबंधित जोखिमों का आकलन और मूल्य निर्धारण; ई-मनी जारीकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थी खातों की बढ़ती प्रासंगिकता; और तीसरे पक्ष की भागीदारी। इसके अलावा, नए व्यवसाय मॉडल नए जोखिमों को जन्म देते हैं या मौजूदा जोखिमों की प्रासंगिकता को बढ़ा सकते हैं। डिजिटलीकरण में साइबर सुरक्षा जोखिम भी शामिल है। आवश्यक तकनीकी अवसंरचना की अनुपलब्धता या ऐसे अवसंरचना के विरुद्ध अनैतिक गतिविधि से जमा बीमाकर्ताओं की व्यावसायिक निरंतरता महत्वपूर्ण रूप से बाधित होने की संभावना है।

मुद्राओं और भुगतान प्रणालियों में दो डिजिटल नवाचार विशेष ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि दोनों का जमा बीमा पर प्रभाव पड़ता है। इसमें से एक है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जो केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक वैध मुद्रा या फिएट मुद्रा है। सीबीडीसी के प्रमुख लाभ लेन-देनों की अंतिमता (बैंक मध्यस्थता न होने के कारण निपटान जोखिम समाप्त हो जाता है) और रियल टाइम तथा भुगतान प्रणालियों का लागत प्रभावी ढंग से सार्वत्रीकरण है। मध्यम अवधि में, बैंक सुविधा रहित लोगों द्वारा सीबीडीसी को अपनाने से वित्तीय समावेशन में वृद्धि हो सकती है। कई केंद्रीय बैंकों को लोगों द्वारा निजी या डिजिटल साधनों, जो घरेलू मुद्रा द्वारा समर्थित या उसमें मूल्यांकित नहीं होते हैं, के बड़े पैमाने पर उपयोग से जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की देनदारी और डिजिटल नकदी का एक रूप होने के कारण इस जोखिम को कम करने में सहायता कर सकती है। जनता के लिए वह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नकदी और कुछ हद तक बैंक जमा जैसे निजी धन का विकल्प हो सकती है।

जमाराशि पर सीबीडीसी का प्रभाव और उसके चलते जमा बीमा पर उसके प्रभाव का काफी हद तक आज भी अंदाज नहीं है। प्रत्येक क्षेत्राधिकार विशेष की सीबीडीसी ऑपरेटिंग मॉडल और डिज़ाइन विशेषताएँ जोखिमों के संतुलन के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक होंगी। जमा बीमाकर्ताओं के लिए बड़ी जिज्ञासाएं यह हो सकती हैं कि बैंक जमाराशि के बदले सीबीडीसी की हिस्सेदारी कितनी होगी, केंद्रीय और वाणिज्यिक बैंकों के बीच श्रम का विभाजन और सीबीडीसी के उपयोग से जुड़ी गोपनीयता का स्तर क्या होगा। उन्हें इस संभावना से भी जूझना होगा कि जमाकर्ताओं में घबराहट पैदा करने वाले संकटों के दौरान सीबीडीसी को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में माना जा सकता है, जिससे बैंक जमाराशि, विशेषकर बिना बीमा वाली जमाराशि, निकासी के लिए अधिक प्रवण हो सकती है और परिणामत: बैंक रन का जोखिम हो सकता है। ऐसी प्रणालियों और जमा बीमाकर्ताओं के उद्देश्यों और संचालनों के बीच अंतर्निहित संबंधों को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि सीबीडीसी का विषय जमा बीमाकर्ताओं और आईएडीआई के लिए प्रासंगिकता के रूप में बढ़ता रहेगा, जिससे समय-समय हो रही गतिविधियों और नीति विचार-विमर्श बनाए रखने की आवश्यकता बनी रहेगी।

दूसरा, डिजिटल भुगतान क्षेत्र एक मौन क्रांति से गुजर रहा है। आज 70 से अधिक देशों में, त्वरित भुगतान प्रणालियों (आईपीएस) की बढ़ती उपलब्धता के कारण घरेलू भुगतान प्रेषक या प्राप्तकर्ता के लिए लगभग शून्य लागत पर कुछ ही क्षणों में अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं।[1] जमा बीमाकर्ताओं को इन 24/7 भुगतान प्रणालियों के उद्भव से जमाकर्ताओं और सदस्य बैंकों के लिए उत्पन्न परिचालन जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ रहा है। डिजिटल नवाचार वित्तीय सेवाओं की सीमा पार आपूर्ति को आसान बना सकते हैं, लेकिन वे गैर-घरेलू जमाकर्ताओं की एक बड़ी हिस्सेदारी वाले सदस्य बैंकों से उनका जोखिम भी बढ़ा सकते हैं और बैंक डिफ़ॉल्ट के बाद भुगतान के मामले में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वास्तव में, सीमा पार बैंकिंग गतिविधियों का बढ़ता दायरा बढ़ जाने से जमा बीमाकर्ताओं और अन्य वित्तीय सुरक्षा संस्था प्रतिभागियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग अधिक जरूरी बन जाता है।

### 3. टोकनयुक्त जमाराशि

ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग और उपयोग ने टोकनयुक्त जमाराशि या सुरक्षित ब्लॉकचेन पर होस्ट किए गए पारंपरिक बैंक जमाराशि के डिजिटल रूप को गति दी है। टोकनीकरण और यूनिफाइड लेजर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के "फ़िन्टरनेट"[2] दृष्टिकोण के

[1] https://www.bis.org/about/bisih/topics/fmis/nexus.htm

लिए भी केंद्रीय हैं। जमाराशि टोकन दो प्रकार के हो सकते हैं: 1) वाहक-जैसे लिखत जो हस्तांतरणीय हैं; और 2) गैर-हस्तांतरणीय दावे जो केंद्रीय बैंक मुद्रा या थोक सीबीडीसी में निपटाए जाते हैं। उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से टोकनयुक्त जमाराशि को विभिन्न प्रणालियों के साथ अंतर-संचालन योग्य होना चाहिए, अन्य प्रकार की मुद्रा के समान ही उसमें विश्वास और भरोसा होना चाहिए और "मुद्रा का एकल मूल्य"[3] गुण का भी पालन होना चाहिए – अर्थात मुद्रा के अन्य रूपों के समान ही उसका मूल्य हो। टोकनयुक्त जमाराशि के घरेलू और सीमा-पार भुगतान, व्यापार और निपटान, और नकद संपार्श्विक के लिए विभिन्न उपयोग के मामले हो सकते हैं। वास्तव में, प्रोग्राम करने योग्य होने के कारण, उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सहजता से इस्तेमाल किया जा सकता है, भुगतान जानकारी और भुगतान मूल्य को मिलाकर "एटोमिक" निपटान[4] किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो टोकनयुक्त जमाराशियाँ तरलता बढ़ा सकती हैं, लागत में कमी ला सकती हैं, बेहतर पहुँच (24×7) प्रदान कर सकती हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप और त्वरित निपटान के लाभ प्रदान कर सकती हैं। बीआईएस परियोजना अगोरा[5] (ग्रीक में "बाज़ार") यह पता लगाएगा कि टोकनीकरण मौद्रिक प्रणाली के कार्य को कैसे बढ़ा सकता है।

टोकनीकरण से जुड़े विनियामक और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों में दबाव के समय में बैंक रन बढ़ने की संभावना; यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्था कि टोकनयुक्त जमाराशियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पारंपरिक जमाराशियों के रूप में माना जाता है, जिसमें जमा बीमा; परिचालन जोखिम और साइबर सुरक्षा चिंताएँ शामिल हैं; और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने और संकटग्रस्त बैंकों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी समाधान संबंधी मुद्दे शामिल हैं।

जमा बीमाकर्ताओं को यह देखते हुए कि टोकनयुक्त जमाराशियाँ अनिवार्य रूप से अन्य प्रकार की जमाराशियों की तरह जारीकर्ता बैंकों पर दावे हैं, अपने अधिदेश और कवरेज को संशोधित करने के तरीके पर विचार करके टोकनयुक्त जमाराशियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा, निधि के आकार और प्रीमियम दरों को निर्धारित करने के लिए टोकनयुक्त जमाराशियों द्वारा उत्पन्न जोखिमों का खाका तैयार किया जाना चाहिए। इनका समाधान और दावा प्रक्रिया के तौर-तरीकों के चयन पर भी असर होगा, क्योंकि अलग-अलग बैंक अलग-अलग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही यह संभावना भी है कि टोकनयुक्त जमाराशि ऐसे जमाकर्ताओं द्वारा रखी जा सकती है जिन्होंने केवाईसी का अनुपालन नहीं किया हो और जो जारीकर्ता बैंकों के ग्राहक न हों। नतीजतन, दावों की प्रामाणिकता और वास्तविकता का सत्यापन एक कठिन चुनौती साबित हो सकता है।

**4. जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिम**

वर्ष 2023 अभी तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष था और 2024 इससे भी अधिक गर्म हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हम पर हावी हो रहा है, मानवजाति और पृथ्वी को खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण *ग्रीन स्वान* घटनाएँ बढ़ती तीव्रता के साथ फिर से होने की संभावना है। भौतिक जोखिमों और संक्रमण जोखिमों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे पहले से ही गंभीर जलवायु घटनाओं से आर्थिक लागतों और वित्तीय घाटे की बढ़ती घटनाओं से बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के तुलनपत्र और संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ शुद्ध शून्य लक्ष्यों की ओर बढ़ रही हैं, बैंकों पर नीतिगत परिवर्तनों, प्रौद्योगिकीय विकासक्रमों और पर्यावरण, सामाजिक तथा अभिशासन (ईएसजी) लक्ष्यों से प्रभावित निवेशक और उपभोक्ता वरीयताओं से संक्रमण जोखिमों का और भी अधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए 18 सिद्धांत जारी किए हैं। कुछ केंद्रीय बैंक और विनियामक विनियमित संस्थाओं के बीच जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए मौद्रिक नीति रणनीतियों और विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों के ढांचे को सूचित करने के उद्देश्य से जलवायु दबाव परीक्षणों के डिजाइन बनाने और संचालन में लगे हुए हैं।

जमा बीमा के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम पारंपरिक जोखिमों से इस मायने में अलग हैं कि इसके लिए प्रभावी बीमा योजनाएँ और हेजिंग साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ग्रीन टैक्सोनॉमी के विकास और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण इन जोखिमों का मॉडलिंग

[2] https://www.bis.org/publ/work1178.htm

[3] https://www.bis.org/publ/bisbull73.htm

[4] डिलीवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) के ब्लॉकचेन समकक्ष। टोकन और आस्ति जिसके लिए भुगतान किया जाता है, उसे एक साथ अंतरित किया जाता है।

[5] https://www.bis.org/press/p240403.htm

चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से मूल्य शृंखला या स्कोप 3 उत्सर्जन के उत्सर्जन पर। फिर भी, जैसे-जैसे प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं और गंभीरता बढ़ती है और वित्तीय स्थिरता के विचार दायरे में आती हैं, जमा बीमाकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे उन संस्थानों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव का सक्रिय रूप से आकलन और समाधान करने के लिए तैयार रहें जो उनके कार्य के अधीन आते हैं। वास्तव में, आईएडीआई के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश जमा बीमाकर्ता ईएसजी की प्रासंगिकता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जिसका शुद्ध दावा राशि और समाधान लागत पर प्रभाव पड़ता है। जमा बीमाकर्ताओं द्वारा निधि प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसे जलवायु अनुकूल विकल्प शामिल किए जा सकते हैं जो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

जमा बीमाकर्ता कुछ विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि जलवायु जोखिम आधारित प्रीमियम, निधियों का जलवायु दबाव परीक्षण, तथा निधि प्रबंधन, जोखिम निगरानी और समाधान योजनाओं में स्थिरता के तत्वों का निर्माण।[6] इसके अलावा जमा बीमाकर्ताओं, विनियामकों और उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझाकरण से वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जलवायु जोखिम का सामना करने में सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

## 5. संकटकालीन तैयारी और कारोबार निरंतरता प्रबंधन को बेहतर बनाना

यह स्पष्ट है कि पारंपरिक जोखिमों के अलावा, इसके पहले उल्लिखित नए जोखिम, जमा बीमाकर्ताओं और अन्य वित्तीय सुरक्षा समूह प्रतिभागियों के लिए संकटकालीन तैयारी और प्रबंधन के लिए रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य बनाते हैं ताकि संभावित संक्रामक प्रभावों को कम किया जा सके और जमा स्वीकार करने वाले संस्थानों की विफलता को प्रबंधित करने की क्षमता बढ़ सके। संकट तेजी से फैलते हैं, इसलिए संकटग्रस्त संस्थानों में आपातकालीन चलनिधि सहायता और पूर्व-निवारक हस्तक्षेप के बेहतर प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।

"आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन में जमा बीमाकर्ता की भूमिका" पर आईएडीआई का कोर सिद्धांत क्र. 6 बैंक विफलताओं और अन्य विनाशकारी घटनाओं की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं का सुझाव देता है। इसके अलावा, जैसा कि इसमें बताया गया है, प्रणालीगत संकट तैयारी रणनीतियाँ और प्रबंधन नीतियाँ सभी सुरक्षा समूह प्रतिभागियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनके बीच समन्वय आवश्यक है। कोर सिद्धांत क्र.4 अन्य सुरक्षा समूह प्रतिभागियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर देता है। कोर सिद्धांत क्र.9 में यह सिफारिश की गई है कि जमा बीमा प्रणाली के लिए आपातकालीन वित्तपोषण व्यवस्था - जिसमें चलनिधि वित्तपोषण के पूर्व-नियोजित और सुनिश्चित स्रोत शामिल हैं - को कानून या विनियमन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है (या अनुमति दी जा सकती है), जिसमें बाजार उधारी भी शामिल है। जमा बीमाकर्ताओं द्वारा इन दिशानिर्देशों को सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए और उभरते जोखिमों से निपटने के लिए टूलकिट तैयार करना चाहिए।

## 6. निष्कर्ष

अंत में, मैं इन नई चुनौतियों के संदर्भ में भारत में जमा बीमा के परिचालन के माहौल के बारे में बात करना चाहूँगा। भारत ने 01 नवंबर 2022 से थोक सीबीडीसी (e₹-W) और 01 दिसंबर 2022 से खुदरा सीबीडीसी (e₹-R) के लिए एक पायलट शुरू किया। भारत दुनिया भर में फैल रही डिजिटल क्रांति में अग्रणी रहने के लिए अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दे रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) चौबीसों घंटे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन अंतरण सुविधा देता है और एक ही ऐप के तहत कई बैंक खातों और विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। भारत सीमा पार भुगतान को तत्काल और कुशल बनाने के लिए यूपीआई को अन्य देशों की जल्द भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। आरबीआई **प्रोजेक्ट नेक्सस** में शामिल हुआ है, जो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के एफपीएस को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बीआईएस के **इनोवेशन हब** द्वारा

[6] जमा बीमाकर्ताओं के निधि प्रबंधन में जलवायु की भूमिका पर आईएडीआई सर्वेक्षण टिप्पणी, 2023।

परिकल्पित एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। जलवायु की बात करें तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल किया जाएगा, और साथ ही अन्य जलवायु लक्ष्य भी शुद्ध शून्य से पहले हासिल किए जाएंगे। आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा और 2024 में जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर एक प्रकटीकरण रूपरेखा जारी की है, जिसमें जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी कर रही है।

यह परिवर्तन डीआईसीजीसी की छह दशकों की यात्रा में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। अपने "पेबॉक्स प्लस" अधिदेश के तहत, निगम को जमा निकासी पर प्रतिबंध के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर (यहां तक कि परिसमापन या समामेलन से पहले) दावों का अंतरिम भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। 31 मार्च 2024 तक 376,661 जमाकर्ताओं को ₹5359 करोड़ (लगभग 640 मिलियन यूएसडी) की राशि का अंतरिम भुगतान किया गया। डीआईसीजीसी के दायरे में 1997 बैंक शामिल हैं, जिनमें 140 वाणिज्यिक बैंक और 1,857 सहकारी बैंक शामिल हैं और यह दुनिया में जमा बीमा द्वारा कवर किए जाने वाले जमा स्वीकार करने वाले संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या में, और अमेरिका के बाद, दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में, जमा बीमा कवरेज सीमा (₹500,000 या लगभग यूएसडी 6,000), जमा खातों के 97.8 प्रतिशत और जमा मूल्य के 43.1 प्रतिशत को पूरी तरह से सुरक्षित करती है। उभरती चुनौतियों के संदर्भ में, डीआईसीजीसी आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन ढांचे सहित जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दे रहा है। सभी परिचालनों का डिजिटल परिवर्तन चल रहा है। जन जागरूकता अभियानों को नया रूप दिया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। जलवायु जोखिम पर अधिक ध्यान देते हुए ईएसजी नीति पर काम को प्राथमिकता दी जा रही है।

वैश्विक वित्तीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। जमा बीमाकर्ताओं और अन्य वित्तीय सुरक्षा समूह प्रतिभागियों के लिए इन बड़े बदलावों के बीच विद्यमान समय से आगे रहने की चुनौती है। मुझे यकीन है कि अगले दो दिनों में आपके विचार-विमर्श से उभरती चुनौतियों के बारे में हमारी सामूहिक समझ बढ़ेगी ताकि हम जनता का विश्वास बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में प्रासंगिक और सार्थक बने रहें।

मैं सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।